High an Islusion The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1--- खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

C. J.

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115]

नई दिल्ली, बुघवार, जुलाई 1, 1970/ झावाब 10, 1892

No. 115]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1970/ASADHA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Administrative Reforms)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st July 1970

No. 8/4/70-P.—The Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) appointed on 5th January 1966, the Administrative Reforms Commission to give consideration to the need for ensuring the highest standards of efficiency and integrity in the public services and for making public administration a flt instrument for carrying out the social and economic policies of the Government and achieving social and economic goals of development, as also one which is responsive to the people.

- 2 The Administrative Reforms Commission ceased to function with effect from the afternoon of 30th June, 1970, after presenting 20 reports to the Government on various aspects of public administration.
- 3. Government wish to take this opportunity to place on record their high appreciation of the work done by the Commission.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories etc.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

L. P. SINGH, Secy

गृह मंत्रालय

(प्रशासनिक सुधार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1970

सं० 8/4/70-पी०. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) ने लोक सेवाघों में सर्वोच्च स्तर की दक्षता तथा सत्यनिष्ठा को सुनिष्चित करने की श्रावश्यकता पर विचार करने, सरकार की सामाजिक ग्रीर श्रार्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने, सामाजिक तथा श्राधिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने ग्रीर लोगों की भावनाग्रों को समझने में उसे समर्थ बनाने के हेतु लोक प्रशासन को उपयुक्त साधन बनाने के लिए 5 जनवरी, 1966 को प्रशासनिक सुधार श्रायोग की नियुक्ति की थी।

- 2. प्रशासनिक सुधार श्रायोग ने लोक प्रशासन के विभिन्न पहलुश्रों पर सरकार को 20 रिपोर्टें प्रस्तुत करने के बाव 30 जून, 1970 (श्रपरान्ह) से कार्य करना बन्द कर दिया।
- 3. श्रायोग ने जो कार्य किया है उसके लिए सरकार इस अवसर पर श्रायोग के प्रति उक्तिट सराहना की भावना प्रकट करती है।

मावेश

श्रादेश दिया जाता है कि ६स संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार क सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ग्रादि को भेजी जाए।

यह भी भ्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भ्राम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

ल० प्र० सिंह, सचिव ।

